भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1561

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर प्रयोगशालाएं और इंटरनेट

†1561. **श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:**
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्री एंटो एन्टोनी:
श्री के. सुधाकरन:
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यात्मक कंप्यूटर प्रयोगशालाओं और इंटरनेट संपर्क से युक्त सरकारी विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संचालित सरकारी विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उन सरकारी विद्यालयों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) या डिजिटल साक्षरता मॉड्यूल को शामिल किया है;
(ग) क्या सरकार ने विद्यालय स्तर पर एआई शिक्षा को एकीकृत करने के लिए कोई राष्ट्रीय दिशानिर्देश या शिक्षण मानदंड जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) एआई-संबंधित शिक्षण में प्रशिक्षित सरकारी विद्यालय शिक्षकों की संख्या कितनी है और क्या विषय-विशिष्ट क्षमता निर्माण ऐसे प्रशिक्षण का हिस्सा है और यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने एआई या डिजिटल साक्षरता मॉड्यूल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कोई अधिगम परिणाम आकलन आयोजित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार देश में असमान डिजिटल अवसंरचना और शिक्षक प्रशिक्षण से उत्पन्न डिजिटल सुविधाओं की बढ़ती कमी को रोकने के लिए क्या योजना बना रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): यूडाइज + (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा VI और उससे ऊपर के सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या और इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब और इंटरनेट सुविधा का प्रतिशत https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और स्कूल पाठ्यक्रम में इसकी भूमिका के महत्व पर ज़ोर दिया है। नीति के पैरा 4.24 में बताया गया है कि "सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी) जैसे समकालीन विषयों को शामिल करने सहित, समन्वित पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पहल की जाएंगी।"

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने ग्रेड 11 और 12 के लिए एआई के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के लिए एक पाठ्यपुस्तक विकास टीम का गठन किया है। एनसीईआरटी ने ग्रेड 6 के लिए व्यावसायिक शिक्षा की पाठ्यपुस्तक में एनिमेशन और गेम्स पर एक परियोजना को भी शामिल किया है। इस परियोजना में एआई टूल्स का उपयोग शामिल है। कंप्यूटर साइंस कक्षा XI (अध्याय 3, https://ncert.nic.in/textbook.php?kecs1=ps-11) और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कक्षा XI (अध्याय 2, https://ncert.nic.in/textbook.php?keip1=ps-8) की मौजूदा एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में एआई, आईओटी और अन्य उभरती हुई प्रोद्योगिकियों के बारे में बताया गया है।

भारत सरकार ने एसओएआर (स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस) आरंभ किया है, जो एनईपी 2020 के उद्देश्यों, राष्ट्रीय एआई कार्यक्रम (एनपीएआई) कौशल रूपरेखा और डिजिटल सशक्तीकरण के विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने वाली एक राष्ट्रीय पहल है। एसओएआर का उद्देश्य स्कूली छात्रों (कक्षा 6-12) के बीच एआई जागरूकता और बुनियादी क्षमताएं पैदा करना और शिक्षकों के बीच एआई साक्षरता का निर्माण करना है। एसओएआर पाठ्यक्रम में चार प्रगतिशील राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसएफ़क्यू) के अनुरूप मॉड्यूल शामिल हैं। कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए, तीन अलग-अलग माइक्रो-क्रेडेंशियल: (i) एआई टू बी अवेयर, (ii) एआई टू एक्वायर, और (iii) एआई टू एस्पायर, प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक 15 घंटे की अवधि का है, कुल मिलाकर 45 घंटे। इनमें बुनियादी एआई अवधारणाएं, व्यावहारिक प्रोग्रामिंग, नैतिक और जिम्मेदार एआई उपयोग, और प्रौद्योगिकी में करियर के अवसर शामिल हैं। शिक्षकों के लिए, एआई फॉर एजुकेटर्स नामक 45 घंटे का मॉड्यूल एआई अवधारणाओं, शैक्षणिक कार्यनीतियों और व्यावहारिक कक्षा अनुप्रयोग में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है।

शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा स्तर पर अधिगम के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वित कर रहा है। इसके लिए 'नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स' और 'टीचर्स

होलिस्टिक एडवांसमेंट' (निष्ठा) नाम का एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निष्ठा के ज़रिए, राष्ट्रीय संसाधन समूह को शिक्षा प्रोद्योगिकियों में प्रशिक्षण दिया जाता है और डिजिटल शिक्षकों को प्रमाणित किया जाता है।

इसके अलावा, एआई जैसी नई प्रोद्योगिकियों के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने नीचे दी गई कई पहलें शुरू की हैं: -

- एनईपी 2020 को लागू करना, जो बहुविषयक , प्रोद्योगिकी-एकीकृत अधिगम पर ज़ोर देती है, जिसमें स्कूल स्तर से ही कोडिंग, एआई, डेटा साइंस, डिज़ाइन थिंकिंग, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और अनुभवात्मक अधिगम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- उद्योग और तकनीकी एजेंसियों के साथ समन्वय से ऑनलाइन एआई सीरीज़, वर्कशॉप और प्रशिक्षण के ज़रिए शिक्षकों और छात्रों के लिए देश भर में क्षमता –निर्माण कार्यक्रम ।
- हितधारकों के साथ नियमित क्षमता निर्माण/परामर्श वर्कशॉप आयोजित करना। इन वर्कशॉप का उद्देश्य नवाचारी , शिखन –विशिष्ट एआई समाधान की पहचान करना और ज़िम्मेदार एआई प्रयोग में उत्तम प्रथा को समझना है। दीक्षा टीम कक्षा निर्देशों , आकलन और व्यक्तिगत अधिगम में शिक्षकों की मदद करने के लिए नए एआई-आधारित विशेषताओं और टूल्स को शामिल करने पर भी लगातार कार्य कर रही है।

  • शिक्षकों को संवेदनशील बनाने/ओरिएंटेशन सत्र शिक्षकों और शैक्षणिक टीमों को एआई की क्षमताओं, सीमाओं, नैतिक बातों और सुरक्षित इस्तेमाल के दिशानिर्देशों को समझने में मदद करते हैं, जिससे वे एआई टूल्स को अपने शिक्षण के तरीकों में जिम्मेदारी से एकीकृत कर पाते हैं।

(ङ): भारत सरकार देश भर में अधिगम और शैक्षिक परिणामों को मापने के लिए समय-समय पर बड़े पैमाने पर आकलन करती है। इसी संबंध में, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत राष्ट्रीय आकलन केंद्र - परख, एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से समझने और आकलन के परिणामों की बेहतर व्याख्या करने के लिए, सर्वेक्षण के हिस्से के तौर पर कई संदर्भ से जुड़े आयामों के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई थी। ऐसे संदर्भ से जुड़े आयामों में घर और स्कूल में डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट तक पहुंच शामिल थी।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की रिपोर्ट, जो स्टेज-विशिष्ट योग्यताओं की उपलब्धि और प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले संदर्भ से जुड़े आयामों के बारे में जानकारी देती हैं, https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं, यह एक विशेष डैशबोर्ड है जिसे आकलन के परिणामों के प्रसार के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(च): 17 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के हिस्से के रूप में पीएम ई विद्या नाम की एक बड़ी पहल शुरू की गई थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत पूरे देश

में शिक्षा तक मल्टी-मोड पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एक साथ लाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) एनसीईआरटी के साथ समन्वय से अपनी ज़रूरतों के अनुसार मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में इन पहलों का उपयोग, निगरानी और आकलन करते हैं। पीएम ई विद्या में भारत सरकार में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /स्वायत्त निकायों (एबी)/अन्य मंत्रालयों को आवंटित 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि वे कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपनी ज़रूरत के अनुसार पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) राष्ट्र का वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंट प्रदान करता है, साथ ही सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोड वाली एनर्जाइज़्ड पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) भी प्रदान करता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों /स्वायत्त निकायों ने मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.7 लाख से अधिक सामाग्री निर्मित की है और योगदान दिया है, जिससे बहुभाषावाद संभव हुआ है। दीक्षा ऑफलाइन उन क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है जहाँ इंटरनेट पहुँच सीमित या बिल्कुल नहीं है। हितधारकों के पास दीक्षा पर 450 से अधिक वर्चुअल लैब और 100 वर्चुअल कौशल लैब तक पहुँच प्राप्त है।

प्रबंधन पोर्टल के अनुसार, अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 1,79,153 आईसीटी लैब और 1,76,738 स्मार्ट कक्षा रूम स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने बजट 2025 में, दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए 'भारतनेट' परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है।

*****